दिनांक–17.03.2026 को माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

1. बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :–

(i) निदेशक, पंचायती राज विभाग
(ii) विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग
(iii) अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग
(iv) मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन

2. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत PPT का अवलोकन किया गया।

3. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. (a) राज्य में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कुल 2000 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा पूर्ण पंचायत सरकार भवन की संख्या–585, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की संख्या–1215, 172 पंचायतो में चिन्हित स्थल विवादित है तथा 20 पंचायतो में भूमि अतिक्रमित है। 8 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में निविदा प्रक्रियाधीन है, उन पंचायतों की विस्तृत सूची (कारण सहित) पंचायती राज विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन 20 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की भूमि अतिक्रमित है। उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी के साथ क्रियान्वयन एजेंसी के तकनीकी पदाधिकारी समन्वय स्थापित करेंगे एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना

कृ०पृ०उ०

सुनिश्चित करेंगे। LAEO के द्वारा यह भी बताया गया कि मई 2026 तक कुल 1018 (585+433) पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया जाएगा।

(b) इसी प्रकार भवन निर्माण विभाग द्वारा कुल क्रमशः 2615 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण पंचायत सरकार भवन की संख्या–562, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की संख्या–1414 तथा 351 पंचायतो में भूमि अप्राप्त या समस्याग्रस्त तथा 282 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में निविदा प्रक्रियाधीन है, उन पंचायतों की विस्तृत सूची (कारण सहित) पंचायती राज विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अप्राप्त भूमि की सूची पत्र के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को अवगत कराने का निदेश दिया गया तथा 351 पंचायतों में जहाँ पंचायत सरकार भूमि अप्राप्त या समस्याग्रस्त है की सूची भी विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

II. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि LAEO एवं BCD के द्वारा क्रमशः 139 तथा 08 पंचायत सरकार भवन की प्रविष्टि पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी है, जो चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन की अद्यतन प्रगति पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर यथाशीघ्र प्रविष्ट करे। विभागीय संकल्प के आलोक में पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर ही राशि आवंटित की जाएगी। प्रविष्टि नहीं होने के स्थिति में राशि प्रत्यर्पित होने की जवाबदेही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग (BCD) की होगी।

LAEO के द्वारा बताया गया कि पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर प्रविष्टि के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निदेश दिया गया कि पंचायती राज विभाग, LAEO एवं BCD की Technical Team आपस में

लगातार....

समन्वय स्थापित कर पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर प्रविष्टि के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं का अविलंब निराकरण करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालन–स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग)

III. विभाग के द्वारा जाँच दल गठित कर पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण कराया गया है। जाँच दल के द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विधिवत कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया। अबतक LAEO एवं BCD को क्रमशः कुल 35 एवं 29 निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई हेतु भेजा गया है जिसमें से LAEO द्वारा 19 का ATR (Action Taken Report) प्राप्त हुआ है परंतु उक्त ATR पूरी तरह अपूर्ण है। ऐसा लगता है केवल खानापूर्ति किया गया है। BCD द्वारा एक का भी ATR (Action Taken Report) प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशित किया गया कि सभी लंबित ATR (Action Taken Report) विभाग को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में पाई गयी कमियों का निराकरण करते हुए संबंधित अभियंता एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई कर एक सप्ताह के अन्दर पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

IV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक LAEO एवं BCD को क्रमशः 3127.231 करोड़ एवं ₹2159.714 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिसके विरूद्ध LAEO एवं BCD के द्वारा मात्र ₹1924.00 तथा ₹1778.799 करोड़ रूपये की उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलंब पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

V. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को **LAEO** एवं **BCD** के द्वारा क्रमशः **367** एवं **322** निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु **LAEO** एवं **BCD** के स्तर से क्रमशः **67** एवं **112** पंचायत सरकार

भवनों का हस्तांतरण कतिपय कारणों से लंबित है। हस्तांतरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। निदेशित किया गया कि LAEO एवं BCD के कार्यपालक अभियंता संबंधित जिले के DPRO से समन्वय स्थापित कर हस्तांतरण में आ रही त्रुटियों को हल करते हुए एक सप्ताह के अंदर विधिवत पंचायत सरकार भवनों का हस्तांतरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

VI. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि LAEO एवं BCD द्वारा 2000 एवं 2615 पंचायतों में निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध क्रमशः 191 एवं 351 पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त भूमि पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

VII. ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 728 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध मात्र 282 पंचायतों में ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि 01 सप्ताह के अंदर तकनीकी स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ की जा सके। मुख्य अभियंता, LAEO तकनीकी स्वीकृति में अनावश्यक विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करें।

(अनुपालन– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन)

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

लगातार....

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/6144/पं०रा० पटना, दिनांक22/4/2026
प्रतिलिपि :–सभी जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/6144/पं०रा० पटना, दिनांक22/4/2026
प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/6144/पं०रा० पटना, दिनांक22/4/2026
प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/6144/पं०रा० पटना, दिनांक22/4/2026
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः–2प०/पं०स०भ०–09–04/2023/6144/पं०रा० पटना, दिनांक22/4/2026
प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक